भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 885
उत्तर देने की तारीख 04 फरवरी, 2026

तमिलनाडु में डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा वित्तपोषित मोबाइल कनेक्टिविटी

885. श्री सी. एन. अन्नादुरईः
श्री जी. सेल्वमः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु के उन गांवों की संख्या का ब्यौरा क्या है जहां वर्तमान में 4जी मोबाइल कवरेज है;
(ख) डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा वित्तपोषित मोबाइल कनेक्टिविटी योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु में चालू किए गए टावरों का ब्यौरा क्या है और इन प्रतिष्ठानों से कितने गांव लाभान्वित हो रहे हैं;
(ग) तमिलनाडु में भारतनेट परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और आज की स्थिति के अनुसार कितनी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सेवा के लिए तैयार किया गया है;
(घ) क्या सरकार ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु में मौजूदा भारतनेट नेटवर्क का उन्नयन करने और गैर-ग्राम पंचायत गांवों में फाइबर कनेक्टिविटी का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है; और
(ङ) सरकार द्वारा दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों सहित तमिलनाडु के सभी गांवों में 100 प्रतिशत मोबाइल और ब्रॉडबैंड कवरेज सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) दिसंबर-2025 तक, तमिलनाडु में 16,452 गांवों को 4जी मोबाइल सेवाओं से कवर किया गया है

(ख) से (ङ) देश के दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों के सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए डीबीएन द्वारा वित्त पोषित 4जी मोबाइल सेवा के सेचुरेशन की परियोजना

कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें तमिलनाडु शामिल हैं। इस 4जी सेचुरेशन स्कीम के तहत, दिसंबर-2025 तक, तमिलनाडु में 297 गांवों को कवर करते हुए 255 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं।

भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि तमिलनाडु सहित देश में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। दिसंबर 2025 तक तमिलनाडु में भारतनेट परियोजना के तहत 10,869 जीपी, देश में सेवा प्रदान करने के लिए तैयार की गई हैं। इसके अलावा संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को सरकार द्वारा 04.08.2023 को अनुमोदित किया गया था, जो भारतनेट चरण-I और चरण-II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, शेष जीपी में नेटवर्क के निर्माण और उनके संबंधित जीपी से मांग के आधार पर शेष गैर-जीपी गांवों को कनेक्टिविटी के लिए कार्यान्वयन के अधीन है।

****